VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

Weekly Focus #120

महानगरों से परे:

भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों का विकास

भारत, विश्व की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2047 में भारत अपनी **स्वतंत्रता के 100 वर्ष** पूरे करेगा, और इस उपलक्ष्य में **भारत की आकांक्षा 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था** बनने की है। इस विकास प्रक्रिया में भारतीय शहर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। **भारतीय शहर देश की केवल 3.0% भूमि पर ही बसे हैं, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उनका व्यापक योगदान है,** जो कि 60% से अधिक है। चूंकि, भारत मुख्य रूप से ग्रामीण समाज से शहरी समाज में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए सभी बड़े या छोटे शहरों की आर्थिक क्षमता का अनुकूलतम उपयोग अनिवार्य है। इसे प्राप्त करने के लिए, **हमें न केवल बड़े शहरों और उनके भीतरी क्षेत्रों को आर्थिक संवृद्धि के केंद्र के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है,** बल्कि भविष्य में टियर-2 और टियर-3 शहरों को भी आर्थिक संवृद्धि का केंद्र बनाने की आवश्यकता है।

इस डॉक्यूमेंट में हम निम्नलिखित पर चर्चा करेंगे:

1. हम भारत के शहरों का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं? 2
2. वर्तमान समय में, भारत में टियर-2 और टियर-3 शहरों के उदय के क्या कारण हैं? 2
3. टियर-2 और टियर-3 शहरों से जुड़ी मुख्य चुनौतियां क्या हैं? 4
4. टियर-2 और टियर-3 शहरों में विकास को बढ़ावा देने से राष्ट्रीय विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता मिल सकती है? 5
5. सरकार द्वारा टियर-2 और टियर-3 शहरों में संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी पहलों का कार्यान्वयन किया गया है? 5
6. टियर-2 व टियर-3 शहरों में प्रगति एवं विकास को तीव्र करने के लिए और कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? 7

निष्कर्ष 8
टॉपिकः एक नज़र में 9
बॉक्स, चित्र और टेबल 10

1. हम भारत के शहरों का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं?

भारतीय शहर विविधतापूर्ण और जटिलता से युक्त हैं। इसलिए, भारतीय शहरों का वर्गीकरण करने के लिए जनसंख्या, आर्थिक गतिविधि, अवसंरचना और प्रशासनिक महत्त्व जैसे विविध कारकों पर विचार करना आवश्यक है।

- हालांकि, इसके लिए **कोई एकल "आधिकारिक" वर्गीकरण प्रणाली मौजूद नहीं है। इसके लिए अलग-अलग संगठन विविध मानदंडों और पद्धतियों का उपयोग** करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, शहरों के वर्गीकरण की कई सूचियां और श्रेणियां मिलती हैं।
- 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित वर्गीकरण को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। इस वर्गीकरण को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रकाशित किया था।
    - यह वर्गीकरण **जनसंख्या के आकार के आधार पर शहरों को छह श्रेणियों में वर्गीकृत** करता है। इन श्रेणियों का वर्गीकरण शहर के आकार और उनकी संवृद्धि के चरणों की सामान्य समझ के अनुरूप किया गया है।

बॉक्स 1.1: जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण

टियर	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	उदाहरण
टियर-1	1,00,000 और उससे अधिक	दिल्ली, मुंबई
टियर-2	50,000 से 99,999	जयपुर, भोपाल
टियर-3	20,000 से 49,999	सलेम, रुड़की
टियर-4	10,000 से 19,999	बांसवाड़ा, कल्याणी
टियर-5	5,000 से 9,999	बड़े ग्रामीण केंद्र
टियर-6	5,000 से कम	छोटी ग्रामीण बस्ती

- **टियर-1 शहर:** ये शहर मुख्य तौर पर व्यापार, राजनीति और सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, इनमें अधिक आबादी, सुदृढ़ अवसरंचना, मजबूत आर्थिक आधार, उच्च जीवन स्तर और सुव्यवस्थित स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां होती हैं।
- **टियर-2 और टियर-3 शहर:** इनमें वे शहर शामिल हैं, जिनमें रोजगार, निवेश, व्यापार, अनुसंधान और शिक्षा जैसी आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जा रही है।
- **अन्य शेष श्रेणियों के शहर आमतौर पर दूरस्थ या ग्रामीण क्षेत्रों** में स्थित हैं। अक्सर इन दूरस्थ शहरों का देश के अन्य हिस्सों से मजबूत कनेक्टिविटी का अभाव होता है।

2. वर्तमान समय में, भारत में टियर-2 और टियर-3 शहरों के उदय के क्या कारण हैं?

भारत में टियर-2 और टियर-3 शहरों के उदय के विविध कारक हैं, जो लोगों एवं व्यवसायों को टियर-1 शहरों से बाहर आने के लिए बाध्य कर रहे हैं तथा उन्हें छोटे शहरों की ओर आकर्षित कर रहे हैं।

टियर-1 शहरों के प्रतिकर्ष कारक (Push factors), जो लोगों और व्यवसायों को टियर-1 शहरों से बाहर जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं

- **संतृप्तता और प्रतिस्पर्धा:** जैसे-जैसे टियर-1 शहरों में भीड़ बढ़ती जाती है, वहां **रोजगार, व्यवसाय संवृद्धि और सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता के अवसर सीमित** होने लगते हैं। इसके परिणामस्वरूप, लोग और व्यवसाय बेहतर जीवन स्तर तथा अवसरों की तलाश में छोटे शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं।
- **जीवन यापन की उच्च लागत:** टियर-1 शहरों को अक्सर रहने की उच्च लागत से जोड़ा जाता है। इस लागत में **आवास का अधिक किराया, उच्च परिवहन लागत, अधिक दैनिक खर्च** आदि शामिल होते हैं। यह व्यक्तियों और व्यवसायों को टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में अधिक वहनीय विकल्पों को तलाशने के लिए विवश कर सकता है।
- **पर्यावरणीय असंधारणीयता:** सामान्यत: टियर-1 शहरों को पर्यावरणीय संधारणीयता से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें वायु व जल प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी मुद्दे और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण जैसी चुनौतियां शामिल हैं।
    - उदाहरण के लिए, **2022 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार**, PM2.5 स्तर के आधार पर दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में **दिल्ली का चौथा स्थान** था। इसके अलावा, इंदौर और सूरत जैसे टियर-2 व टियर-3 शहरों को भारत के सबसे स्वच्छ शहरों के रूप में स्थान दिया गया था।
- **अपराध और लोगों की सुरक्षा:** टियर-2 और टियर-3 शहरों की तुलना में टियर-1 शहरों में अपराधों की दर अधिक हो सकती है। इससे लोगों की सुरक्षा का स्तर कम हो सकता है।
    - **2022 की NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, जिन शहरों में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध होते हैं, उन शहरों में दिल्ली** भी शामिल है।

टियर-2 और टियर-3 शहरों से संबंधित अपकर्ष कारक (Pull Factors), जो लोगों एवं व्यवसायों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं

- **प्रतिभाशाली कार्यबल की उपलब्धता:** कुशल एवं शिक्षित कार्यबल की उपलब्धता के कारण टियर-2 और टियर-3 शहरों की ओर आकर्षण बढ़ता जा रहा है।
  - **नैसकॉम (NASSCOM) की एक रिपोर्ट के अनुसार,** तकनीकी प्रतिभा से युक्त भारत का लगभग 15% तक कार्यबल टियर-2 और टियर-3 शहरों में निवास करता है।
- **मध्यम वर्ग की आबादी में वृद्धि:** टियर-2 और टियर-3 शहरों में मध्यम वर्ग का प्रभाव एवं बढ़ती क्रय शक्ति वस्तुओं व सेवाओं की मांग को बढ़ा रही है। इससे टियर-2 और टियर-3 शहरों में बाजार की क्षमता में भी बढ़ोतरी हो रही है।
- **अवसंरचना का विकास:** वर्तमान में टियर-2 और टियर-3 शहरों की अवसंरचना में महत्वपूर्ण विकास हो रहा है। इसमें बेहतर परिवहन नेटवर्क, जीवन के लिए आवश्यक आधुनिक सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी शामिल हैं।
  - **सरकारी प्रयासों** जैसे क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी के लिए **उड़ान योजना** (UDAN Yojna) ने इन शहरों को और अधिक आकर्षक बना दिया है।
- **डिजिटल रूपांतरण में तीव्रता:** टियर-2 और टियर-3 शहर डिजिटल अवसंरचना में भारी निवेश कर रहे है, जैसे हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल भुगतान प्रणाली और ई-गवर्नेंस संबंधी पहलें आदि। इस प्रकार के निवेश इन शहरों को व्यवसाय के लिए और अधिक आकर्षक बना रहे हैं।
  - एक सर्वेक्षण के अनुसार, **ई-कॉमर्स के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 50% ऑनलाइन खरीदार छोटे शहरों से हैं, जो इन शहरों के विकास को गति** दे रहे हैं।
- **अवस्थिति संबंधी तुलनात्मक लाभ:** कई **औद्योगिक क्लस्टर्स** वाले टियर-2 और टियर-3 शहर **व्यापार-अनुकूल राज्यों** में स्थित हैं और ये अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों से **अच्छी तरह** से जुड़े हुए हैं।
  - उदाहरण के लिए, **डेलॉयट रिपोर्ट के अनुसार भारत में 242 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में से 83 और 60 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) केंद्रों में से 15 इन शहरों** में ही स्थित हैं।
- **कोविड का प्रभाव:** कोविड-19 महामारी ने **दूरस्थ कार्य संस्कृति (Remote work culture)** को तीव्र कर दिया है। इस कारण टियर-2 और टियर-3 शहरों की तरफ रिवर्स माइग्रेशन की प्रवृत्ति में तीव्रता आई है। परिणामस्वरूप, इन शहरों ने उन **कंपनियों को नए अवसर** प्रदान किए हैं, जो अपने कार्य संचालन में क्षेत्रीय विविधता लाना चाहते थे।
- **गिग इकॉनमी का उदय:** गिग इकॉनमी के उदय ने इन शहरों में विस्तार की चाह रखने वाली सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कंपनियों के लिए इन शहरों में विस्तार हेतु अवसर उपलब्ध कराए हैं। इसका कारण इन शहरों में वहनीय भूमि और सस्ते श्रम सहित कम परिचालन लागत तथा एक बड़े और स्थिर प्रतिभा पूल की उपस्थिति है, जो उन्हें ऐसी कंपनियों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बनाती है।
  - रिपोर्ट्स के अनुसार, **गिग इकॉनमी में टियर-2 शहरों की महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि** हो रही है।
- **वेयरहाउसिंग संबंधी निवेश के लिए आशाजनक केंद्रों के रूप में उदय:** इसके लिए उत्तरदायी मुख्य कारकों में से एक **वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कार्यान्वयन है।** इस कारक ने **लॉजिस्टिक संचालन को अधिक सुगम** बना दिया है और वस्तुओं की आवाजाही में लगने वाले समय को कम कर दिया है। इससे छोटे शहरों में वेयरहाउसिंग सुविधाएं स्थापित करना अधिक दक्ष व लागत प्रभावी हो गया है।
- **सांस्कृतिक और सामाजिक अवसर:** टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश अच्छी तरह से समृद्ध होता है। साथ ही, ये स्थानीय समुदायों, त्यौहारों और परंपराओं के लिए एक जीवंत परिवेश भी प्रदान करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, ये शहर अधिक समावेशी और समुदाय-उन्मुख जीवन शैली की तलाश कर रहे व्यक्तियों एवं परिवारों को आकर्षित कर रहे हैं।

बॉक्स 2.1: टियर-2 और टियर-3 शहरों में तेजी से बढ़ता स्टार्ट-अप इकोसिस्टम

- वर्तमान समय में स्टार्ट-अप और उद्यमिता केवल महानगरों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। **भारत में लगभग 50% मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स टियर-2 और टियर-3 शहरों** में स्थित हैं।
- ऊपर चर्चित अनुकूल कारकों जैसे जीवनयापन हेतु कम लागत, कौशलयुक्त प्रतिभाशाली मानव संसाधन पूल की उपलब्धता, डिजिटल उन्नति व अवसंरचनात्मक विकास और मध्यम वर्ग के कारण निर्मित नए बाजार के अतिरिक्त कुछ **अन्य महत्वपूर्ण कारक भी हैं, जो छोटे शहरों में स्टार्ट-अप संस्कृति के विकास को बढ़ावा देते हैं। इन कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - **सरकारी पहलें: 'स्टार्ट-अप इंडिया' और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी सरकारी नीतियां** स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के लिए अनुकूल अवसंरचनात्मक समर्थन, प्रोत्साहन एवं संसाधन प्रदान करती हैं।
  - **रिवर्स माइग्रेशन:** जो लोग महानगरों से अपने गृहनगर वापस लौटते हैं, वे अपने साथ **कौशल और अनुभव लेकर आते हैं।** इस कारक ने भी टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
  - **समर्थनकारी स्थानीय सरकारें:** कई टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्टार्ट-अप्स और निवेश को आकर्षित करने के लिए स्थानीय सरकारें अनुकूल नीतियां लागू कर रही हैं। उदाहरण के लिए, इसमें **राजस्थान का iStart कार्यक्रम और केरल स्टार्ट-अप मिशन** (KSUM) शामिल है।
  - **स्थानीय जरूरतों को पूरा करना:** स्थानीय समस्याओं को हल करने और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि जैसे अलग-अलग क्षेत्रकों की समस्याओं के बड़े पैमाने पर समाधान की आवश्यकता स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है।
- **सफलता की कहानियां:**
  - **रेजरपे:** यह पहले कभी एक फिनटेक स्टार्ट-अप था, जो **वर्तमान में एक यूनिकॉर्न** है। यह **पेमेंट गेटवे सेवा** उद्योग में अग्रणी स्थान पर है। इसने 7 मिलियन लोगों को अपनी मातृभाषा में अंग्रेजी सीखने के लिए प्रेरित किया है। यह जयपुर बेस्ड एक स्टार्ट-अप है।
  - **शॉपकिराना:** यह चार राज्यों (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात) के आठ शहरों में 50,000 किराना स्टोर्स के ग्राहकों को बड़े स्तर पर ई-कॉमर्स सेवा प्रदान करता है। **यह इंदौर से है।**
  - **DeHaat:** यह किसानों को व्यापक स्तर पर कृषि सेवाएं प्रदान करने वाला एक प्रौद्योगिकी-संचालित प्लेटफॉर्म है। यह **पटना में अपनी सफलता की कहानी दर्शाता है।**
  - **RodBez:** यह बिहार के रहने वाले दिलखुश कुमार द्वारा शुरू किया गया था। ये बिहार के सहरसा जिले के बनगांव नामक गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने एक रिक्शा चालक और सब्जी विक्रेता के रूप में अपनी आजीविका शुरू की थी, और आज वे बिहार में RodBez नाम से मशहूर स्टार्ट-अप के तहत टैक्सी सेवा प्रदान करते हैं और इस स्टार्ट-अप के मालिक हैं।

3. टियर-2 और टियर-3 शहरों से जुड़ी मुख्य चुनौतियां क्या हैं?

टियर-2 और टियर-3 शहर विकास एवं संस्कृति के केंद्र के रूप में तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो उनकी प्रगति में बाधा बन रही है। **इन चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:**

- **गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का अभाव:**
  - **अपर्याप्त आधारभूत अवसरंचना:** इसके तहत खराब गुणवत्ता वाली सड़कें; अनियमित बिजली आपूर्ति; अपर्याप्त जलापूर्ति और सैनिटेशन सुविधाएं तथा सीमित सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
  - **उच्च गुणवत्तायुक्त डिजिटल अवसंरचना का अभाव:** हाई-स्पीड इंटरनेट की अनुपस्थिति डिजिटल कनेक्टिविटी में एक बड़ी बाधा है। यह बाधा उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न होने वाले संभावित अवसरों को सीमित करती है। उदाहरण के लिए व्यवसायों और नागरिकों हेतु इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रभावित होना।
  - **पुरानी नगर योजना:** टियर-2 और टियर-3 शहरों में अनियोजित शहर विस्तार के परिणामस्वरूप अदक्ष भूमि उपयोग, अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था तथा हरित स्थानों की कमी को बढ़ावा मिलता है।
- **अर्थव्यवस्था और रोजगार:**
  - **रोजगार के सीमित अवसर:** ये शहर मुख्य रूप से पारंपरिक उद्योगों पर केंद्रित हैं। इनमें बड़ी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय निगमों की उपस्थिति सीमित है। इसके अलावा, पर्याप्त कौशल की कमी नौकरियों के विविधीकरण को सीमित करती है।
  - **बेरोजगारी और अल्परोजगार की व्यापकता:** कौशलयुक्त कार्यबल के अक्सर बड़े शहरों की ओर पलायन के कारण छोटे शहरों में कौशल की कमी हो जाती है और आय के अवसर सीमित हो जाते हैं।
  - **अनौपचारिक क्षेत्रक का प्रभुत्व:** यहां की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग अनौपचारिक क्षेत्रक में आता है, जो कि कर संग्रह, विनियमन और श्रमिक लाभ के मामले में चुनौतियों को जन्म देता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा:**
  - **अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और योग्य चिकित्सा पेशेवरों की कमी:** इसके परिणामस्वरूप विशेषज्ञ डॉक्टरों तक सीमित पहुंच, उच्च रोगी-चिकित्सक अनुपात और अस्पतालों एवं क्लीनिकों में खराब बुनियादी ढांचा जैसी समस्याएं सामने आती हैं।
  - **शिक्षा प्रणाली में कमियां:** इन शहरों में गुणवत्तापूर्ण स्कूलों और कॉलेजों की कमी, उच्चतर शिक्षा तक सीमित पहुंच, उच्च ड्रॉपआउट (पढ़ाई बीच में छोड़ना) दर तथा अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण के साथ शिक्षा प्रणाली में व्याप्त कमियां भी एक बड़ी चुनौती है।
  - **डिजिटल विभाजन: सीमित डिजिटल साक्षरता के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन सामग्री की अनुपलब्धता** ऑनलाइन सीखने और शैक्षिक अवसरों में बाधा उत्पन्न करती है।
- **पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दे:**
  - **उच्च प्रदूषण स्तर:** भारत के कई टियर-2 और टियर-3 शहर सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। इन शहरों में न केवल वायु प्रदूषण अत्यंत गंभीर है, बल्कि वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली भी खराब है।
  - **निम्नस्तरीय सैनिटेशन और अपशिष्ट प्रबंधन:** इन शहरों में सैनिटेशन और अपशिष्ट प्रबंधन बेहतर नहीं है। इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ावा मिलता है।
  - **लैंगिक असमानता और सामाजिक भेदभाव:** इन शहरों में पारंपरिक समुदाय और पितृसत्तात्मक मानसिकता की उपस्थिति महिला सशक्तीकरण में बाधा डालते हैं। साथ ही, कुछ समुदायों के लिए विकास के अवसरों को सीमित करते हैं।
- **शासन व्यवस्था एवं प्रशासन:**
  - **सीमित वित्तीय संसाधन:** इन शहरों में स्थानीय सरकारों के समक्ष अक्सर अवसंरचनात्मक विकास और सेवा प्रदायगी के लिए पर्याप्त धन की कमी होती है।
  - **कमजोर संस्थागत क्षमता:** अपर्याप्त मानव संसाधन और कौशल एवं विशेषज्ञता की कमी के कारण शहरी विकास को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना तथा चुनौतियों का समाधान करना मुश्किल हो जाता है।
  - **नागरिक भागीदारी का अभाव:** निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में नागरिकों की सीमित भागीदारी पारदर्शिता और जवाबदेही को कम करती है।

बॉक्स 3.1: टियर-2 और टियर-3 शहरों में पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने में स्थानीय स्वशासन की भूमिका

- टियर-2 और टियर-3 शहर तेजी से संवृद्धि कर रहे हैं, इस संवृद्धि से अवसर तो सृजित हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरणीय चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही हैं। स्थानीय सरकारें इन शहरों को सतत भविष्य की ओर ले जाने की क्षमता रखती हैं।
  - **अपशिष्ट प्रबंधन:** स्थानीय सरकारें प्रभावी अपशिष्ट पृथक्करण, संग्रहण और पुनर्चक्रण प्रणाली का कार्यान्वयन कर सकती हैं। साथ ही, वेस्ट टू वेल्थ (waste-to-wealth) संबंधी पहलों को बढ़ावा भी दे सकती हैं।
  - **सतत नियोजन:** स्थानीय सरकारें हरित स्थानों को विस्तार देने, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने और ऊर्जा-दक्ष इमारतों को प्रोत्साहित करने में व्यापक भूमिका निभा सकती हैं।
  - **जल संरक्षण:** इसके तहत बुनियादी ढांचे की मरम्मत, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा और अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के लिए उपचार संयंत्रों का विकास करने जैसी भूमिका शामिल है।
  - **प्रदूषण नियंत्रण:** स्थानीय सरकारें उत्सर्जन की निगरानी और विनियमन, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और जागरूकता के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
  - **सामुदायिक जुड़ाव:** स्थानीय सरकारें निर्णय निर्माण और हरित पद्धतियों के संदर्भ में नागरिकों को शिक्षित करने तथा शामिल करने में भी व्यापक भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं।
  - **संसाधन जुटाना और सहयोग:** संसाधन और विशेषज्ञता संबंधी कमियों को दूर करने के लिए स्थानीय सरकारें गैर सरकारी संगठनों, निजी संस्थाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी कर सकती हैं।
- उपर्युक्त रणनीतियों को लागू करके स्थानीय स्वशासन संस्थाएं समुदायों को सशक्त बना सकती हैं, संसाधनों को सुरक्षित कर सकती हैं और यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि टियर-2 व टियर-3 शहर आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ, स्वच्छ एवं रहने योग्य बेहतर बनें।

4. टियर-2 और टियर-3 शहरों में विकास को बढ़ावा देने से राष्ट्रीय विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता मिल सकती है?

भारत में टियर-2 और टियर-3 शहरों का विकास अलग-अलग तरीकों से राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

- **क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायक:** टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास से **क्षेत्रीय विकास अधिक संतुलित** हो सकता है। इससे टियर-1 शहरों में आर्थिक गतिविधियों के संक्रेंद्रण में कमी हो सकती है।
- **बेरोजगारी और अल्परोज़गार संबंधी समस्याओं में कमी:** टियर-2 एवं टियर-3 शहरों के बेहतर विकास से विनिर्माण, सेवाओं एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकते हैं।
- **जीवन स्तर में सुधार:** टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में **बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सुविधाओं में सुधार** से इन शहरों के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। साथ ही, समग्र कल्याण में भी सुधार हो सकता है।
- **स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** इन शहरों का विकास रोजगार के नए अवसर पैदा करके, उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर और निवेश को आकर्षित करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी संवर्धित कर सकता है। इससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।
- **सतत विकास लक्ष्य-11 को प्राप्त करने में सहायता:** टियर-2 और टियर-3 शहरों को संधारणीय तरीके से विकसित करना सतत विकास लक्ष्य-11 के अनुरूप है। इस लक्ष्य के तहत **शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, आघात सहनीय और सतत बनाने** का टारगेट निर्धारित किया गया है।
  - इसमें शहरी नियोजन में सुधार, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, आपदाओं के खिलाफ लचीलापन बढ़ाना और सभी निवासियों के लिए बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना आदि शामिल हो सकता है।
- **राष्ट्रीय और वैश्विक एकीकरण:** टियर-2 और टियर-3 शहरों में कनेक्टिविटी एवं पहुंच में सुधार से **व्यापार, निवेश व पर्यटन** को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। यह इन शहरों को **राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक एकीकृत होने में सहायता** भी प्रदान करेगा।
- **नवाचार व उद्यमिता को बढ़ावा:** टियर-2 और टियर-3 शहरों का बेहतर विकास नवाचार एवं उद्यमशीलता के लिए अनुकूल परिवेश बना सकता है। यह नए व्यवसायों और उद्योगों के उदय को बढ़ावा दे सकता है तथा आर्थिक संवृद्धि में भी योगदान दे सकता है।
- **संतुलित शहरीकरण:** इन शहरों का विकास **इन शहरों में अवसर पैदा करके** टियर-1 शहरों की तरफ हो रहे प्रवास की प्रवृत्ति को उलट सकता है। इससे **टियर-1 शहरों के बुनियादी ढांचे और संसाधनों पर दबाव कम** हो सकता है।

5. सरकार द्वारा टियर-2 और टियर-3 शहरों में संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी पहलों का कार्यान्वयन किया गया है?

टेबल 5.1: टियर-2 और टियर-3 शहरों में संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की गई सरकारी पहलें

अवसंरचना के विकास से संबंधित पहलें	
शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF)	इस निधि का लक्ष्य **देश भर के टियर-2 और टियर-3 शहरों में अवसंरचना के विकास का समर्थन** करना है।
मेट्रो रेल नीति, 2017	इस नीति का लक्ष्य विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में **मेट्रो रेल को सतत विकास, बेहतर गतिशीलता और समावेशी विकास का प्रमुख चालक** बनाना है।
पीएम गति शक्ति	यह **अवसंरचनात्मक कनेक्टिविटी परियोजनाओं के एकीकृत योजना निर्माण तथा समन्वित कार्यान्वयन के लिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी** हेतु एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। इस **योजना से टियर-2 शहरों और प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार** होगा।
उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना, 2016	इस योजना का लक्ष्य **क्षेत्रीय हवाई यात्रा को और अधिक वहनीय बनाने के लिए** देश में (विशेष रूप से टियर-2 व टियर-3 शहरों में) अल्पसेवित (Underserved) एवं असेवित (Unserved) हवाई अड्डों के परिचालन में सुधार करना है।
डिजिटल इंडिया	यह एक फ्लैगशिप सरकारी पहल है। इसका उद्देश्य भारत को **डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना** है। **इसके स्तंभों में शामिल हैं–** डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल साक्षरता, ई-कॉमर्स, फिनटेक, डिजिटल भुगतान आदि।

स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने से संबंधित पहलें	
एक जिला एक उत्पाद योजना (ODOP)	➢ इस पहल को **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश के सभी जिलों में **संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा** देना है।
उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं	➢ यह योजना घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए **विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्रकों को वित्तीय प्रोत्साहन** प्रदान करती है। ▷ इनमें से कुछ योजनाएं टियर-2 और टियर-3 शहरों में टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण एवं फार्मास्युटिकल्स जैसे मजबूत संवृद्धि क्षमता वाले क्षेत्रकों को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
मेक इन इंडिया	➢ इसका उद्देश्य भारत को एक **वैश्विक विनिर्माण केंद्र** बनाना है। यह **महानगरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में भी रोजगार के अवसर** पैदा करने में सहायक है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सहायता देने से संबंधित पहलें	
व्यक्तियों, स्टार्ट-अप्स और MSMEs में नवाचारों को बढ़ावा देना (PRISM)	➢ इस पहल के तहत **नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा** देने के लिए व्यक्तियों, स्टार्ट-अप्स तथा MSMEs को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन व मेंटर सहायता प्रदान की जाती है।
सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP)	➢ यह **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय** द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर **सूक्ष्म और लघु उद्यमों की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना** है। ▷ इस पहल के तहत सफल क्लस्टर्स में **मुरादाबाद पीतल के बर्तन क्लस्टर और करूर साड़ी क्लस्टर** शामिल हैं।
प्रधान मंत्री सूक्ष्म और लघु उद्यम औपचारीकरण (PMFME) योजना	➢ PMFME योजना **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय** द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य **क्रेडिट-लिंक्ड पूंजीगत सब्सिडी, शुरुआती पूंजीगत सहायता तथा मार्केटिंग और ब्रांडिंग समर्थन प्रदान करके मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अपग्रेड करना एवं औपचारिक** बनाना है।
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)	➢ इस पहल का उद्देश्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा **सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए गए ऋणों पर गारंटी कवर** प्रदान करना है। इस प्रकार यह टियर-2 और टियर-3 शहरों में विनिर्माताओं के लिए वित्त तक पहुंच में सुधार करने में सहायता प्रदान करती है।

संधारणीयता को बढ़ावा देने से संबंधित पहलें	
स्मार्ट सिटीज़ मिशन	➢ इसका **लक्ष्य 100 भारतीय शहरों को सतत और समावेशी शहरी परिवेश में बदलना** है। यह स्वच्छ और संधारणीय पर्यावरण को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को लागू करने तथा शहर के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर करने पर केंद्रित है।
स्वच्छ भारत मिशन	➢ यह मिशन एक स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद शहरी वातावरण बनाने के लिए **लोगों के व्यवहार में परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन और जन जागरूकता अभियानों को बढ़ावा** देता है।
कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (अमृत/ AMRUT)	➢ इसका लक्ष्य **देश के 500 शहरों में आधारभूत शहरी अवसंरचनाओं में सुधार** करना है। यह जलापूर्ति, सीवरेज, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

स्टार्ट-अप्स को समर्थन देने से संबंधित पहलें	
स्टार्ट-अप इंडिया	➢ इसका उद्देश्य **विनियमों को सरल बनाना, फंडिंग सहायता प्रदान करना तथा स्टार्ट-अप्स को वृद्धि करने और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने** में सहायता प्रदान करने के लिए विविध सेवाएं प्रदान करना है।
नयूजेन (NewGen) नवाचार और उद्यमिता विकास केंद्र	➢ इसकी स्थापना **शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों और शिक्षकों के बीच नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा** देने के लिए की है।
मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स के लिए कर लाभ	➢ **1 अप्रैल 2016 या उसके बाद निगमित स्टार्ट-अप्स आयकर छूट** के लिए आवेदन कर सकते हैं। ➢ मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स जिन्हें **अंतर-मंत्रालयी बोर्ड प्रमाण-पत्र** प्रदान किया जाता है, उन्हें उनके निगमन के बाद से **दस वर्षों में से लगातार तीन वर्षों की अवधि के लिए आयकर से छूट** दी जाती है।

टेबल 5.2 तेजी से बढ़ते टियर-2 और टियर-3 शहरों के उदाहरण

इंदौर: यह शहर अपनी स्वच्छता और अवसंरचना के कारण एक मजबूत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है।	**जयपुर:** यह एक समृद्ध पर्यटन उद्योग, हस्तशिल्प और पारंपरिक कला को बढ़ावा देने वाले एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
विशाखापत्तनम: यह बढ़ते विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक वाला एक बंदरगाह शहर है, जो बड़े निवेशों को आकर्षित करता है।	**कोच्चि:** यह मजबूत स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रक वाला एक कॉस्मोपोलिटन शहर है। यह जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन रहा है।

6. टियर-2 व टियर-3 शहरों में प्रगति एवं विकास को तीव्र करने के लिए और कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं?

टियर-2 और टियर-3 शहरों में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकारी निकायों, स्थानीय अधिकारियों तथा निजी क्षेत्र सहित अलग-अलग हितधारकों का रणनीतिक व ठोस प्रयास जरूरी है। **टियर-2 और टियर-3 शहरों में संवृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के कुछ संभावित तरीके निम्नलिखित हैं:**

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा:** अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को वित्त-पोषित करने और उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार एवं निजी निवेशकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
- **क्षेत्रक-विशिष्ट प्रोत्साहन देना:** टियर-2 और टियर-3 शहरों में विकास की क्षमता वाले उद्योगों को क्षेत्रक-विशिष्ट लक्ष्य-आधारित प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।
- **निवेश संवर्धन एजेंसियों की स्थापना:** सक्रिय रूप से निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने, निवेशकों की सहायता करने और निवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए समर्पित निवेश संवर्धन एजेंसियों की स्थापना की जानी चाहिए।
- **कौशल विकास और शिक्षा को बढ़ावा**
  - **शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग:** स्थानीय उद्योगों की जरूरतों के अनुसार कार्यक्रम तैयार करने के लिए विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों को एक साथ कार्य करना चाहिए।
  - **क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन सामग्री का निर्माण:** डिजिटल साक्षरता को व्यापक बनाने और बड़े स्तर पर ऑडियंस से जुड़ने के लिए, ऑनलाइन शिक्षा एवं कौशल प्रदाताओं को क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री का निर्माण करने पर विचार करना चाहिए।
- **डिजिटल कनेक्टिविटी**
  - **इंटरनेट अवसंरचना में सुधार:** कनेक्टिविटी बढ़ाने और डिजिटल व्यवसायों का समर्थन करने के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट सहित डिजिटल अवसंरचना में निवेश करना चाहिए।
  - **स्मार्ट सिटी पहल:** शहरी सेवाओं में सुधार करने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को लागू करना चाहिए। इससे उन शहरों को प्रौद्योगिकी का लाभ मिल सकेगा।
- **वित्तीय प्रोत्साहन**
  - **टैक्स से छूट और सब्सिडी प्रदान करना:** टियर-2 और टियर-3 शहरों में निवेश करने का विकल्प चुनने वाले व्यवसायों को कर प्रोत्साहन एवं निवेश सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए।
  - **भूमि आवंटन प्रक्रिया को बेहतर बनाना:** भूमि अधिग्रहण के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिए। साथ ही, औद्योगिक व वाणिज्यिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सुलभ एवं सस्ती भूमि प्रदान करने के लिए नीति का निर्माण किया जाना चाहिए।

- **जीवन की गुणवत्ता में सुधार**
  - **शहरी विकास पर ध्यान देना:** रहने योग्य शहरों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इनमें पार्क, सांस्कृतिक सुविधाओं और मनोरंजक क्षेत्रों जैसी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
  - **वहनीय आवास प्रदान करना:** जनसंख्या में हो रही वृद्धि को समायोजित करने के लिए वहनीय आवासीय परियोजनाओं के विकास को सुविधाजनक बनाना चाहिए।
  - **संधारणीय पद्धतियों को बढ़ावा:** सतत और पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों को लागू करना चाहिए। साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **मार्केटिंग और ब्रांडिंग**
  - **शहरों की ब्रांडिंग करना:** शहरों को एक आकर्षक और गतिशील व्यावसायिक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए मार्केटिंग हेतु प्रभावी अभियानों को विकसित एवं उनका कार्यान्वयन करना चाहिए।
  - **स्थानीय सरकार की भागीदारी को बढ़ावा:** किसी शहर को एक निवेश गंतव्य के रूप स्थापित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए अभियानों में स्थानीय सरकारी अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए।
  - **निवेशकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम:** संभावित निवेशकों तक सक्रिय पहुंच बढ़ाने के लिए मार्केटिंग के लक्ष्य-आधारित प्रयासों, रोड शो और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मिशनों का आयोजन किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

विकसित देश बनने के भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों में संवृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचे, उद्योगों, शिक्षा और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करके, ये शहर आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने, रोजगारों को सृजित करने और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

टॉपिक: एक नज़र में

महानगरों से परे: भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों का विकास

2047 तक भारत की **आकांक्षा 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था** बनने की है। इसे प्राप्त करने के लिए भविष्य में टियर-2 और टियर-3 शहरों को भी आर्थिक संवृद्धि का केंद्र बनाने की आवश्यकता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित वर्गीकरण को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। इस वर्गीकरण को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रकाशित किया था।

भारत में टियर-2 और टियर-3 शहरों के उदय के कारण

- **टियर-1 शहरों के प्रतिकर्ष कारक** (Push factors)
  - **संतृप्तता और प्रतिस्पर्धा:** रोजगार, व्यवसाय संवृद्धि और सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता के लिए।
  - **जीवन यापन की उच्च लागत:** इस लागत में **आवास का अधिक किराया, उच्च परिवहन लागत** आदि शामिल होते हैं।
  - **पर्यावरणीय असंधारणीयता:** इसमें वायु व जल प्रदूषण तथा अन्य कारकों जैसी चुनौतियां शामिल हैं।
  - **अपराध और लोगों की सुरक्षा:** अपराधों की दर अधिक हो सकती है। इससे लोगों की सुरक्षा का स्तर कम हो सकता है।
- **टियर-2 और टियर-3 शहरों से संबंधित अपकर्ष कारक** (Pull Factors)
  - **प्रतिभाशाली कार्यबल की उपलब्धता।**
  - **मध्यम वर्ग की आबादी में वृद्धि:** इससे बाजार की क्षमता में भी बढ़ोतरी हो रही है।
  - **सरकारी प्रयासों से अवसंरचना का विकास।**
  - डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के द्वारा **डिजिटल रूपांतरण में तीव्रता।**
  - **अन्य कारक,** जैसे- अवस्थिति संबंधी तुलनात्मक लाभ, दूरस्थ कार्य संस्कृति (Remote work culture), गिग इकॉनमी का उदय आदि।

टियर-2 और टियर-3 शहरों से जुड़ी मुख्य चुनौतियां

- **गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का अभाव: पुरानी नगर योजना,** खराब गुणवत्ता वाली सड़कें, रेल, डिजिटल कनेक्टिविटी आदि।
- **अर्थव्यवस्था और रोजगार:** रोजगार के सीमित अवसर, अनौपचारिक क्षेत्रक का प्रभुत्व।
- **स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा:** अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और योग्य चिकित्सा पेशेवरों की कमी, शिक्षा प्रणाली में कमियां, सीमित डिजिटल साक्षरता के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन सामग्री की अनुपलब्धता।
- **पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दे:** उच्च प्रदूषण स्तर, निम्नस्तरीय सैनिटेशन और अपशिष्ट प्रबंधन, लैंगिक असमानता और सामाजिक भेदभाव।
- **शासन व्यवस्था एवं प्रशासन:** सीमित वित्तीय संसाधन, कमजोर संस्थागत क्षमता आदि।

सरकार द्वारा टियर-2 और टियर-3 शहरों में संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी पहलों का कार्यान्वयन किया गया है?

- **अवसंरचना के विकास से संबंधित पहलें:** शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF); मेट्रो रेल नीति, 2017; पीएम गति शक्ति; उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना, 2016; डिजिटल इंडिया।
- **स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने से संबंधित पहलें:** एक जिला एक उत्पाद योजना (ODOP); उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं; मेक इन इंडिया।
- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सहायता देने से संबंधित पहलें:** व्यक्तियों, स्टार्ट-अप्स और MSMEs में नवाचारों को बढ़ावा देना (PRISM); सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP), आदि।
- **संधारणीयता को बढ़ावा देने से संबंधित पहलें:** स्मार्ट सिटीज़ मिशन; स्वच्छ भारत मिशन; कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (अमृत/ AMRUT)।
- **स्टार्ट-अप्स को समर्थन देने से संबंधित पहलें:** स्टार्ट-अप इंडिया नयूजेन (NewGen) नवाचार और उद्यमिता विकास केंद्र मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स के लिए कर लाभ।

टियर-2 और टियर-3 शहरों में विकास के जरिए राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करना

- **क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायक:** क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर और बेरोजगारी को कम करके।
- **जीवन स्तर में सुधार:** बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सुविधाओं में सुधार करके।
- **सतत विकास लक्ष्य-11 को प्राप्त करने में सहायता:** टियर-2 और टियर-3 शहरों को संधारणीय तरीके से विकसित करना सतत विकास लक्ष्य-11 के अनुरूप है।
- **राष्ट्रीय और वैश्विक एकीकरण:** टियर-2 और टियर-3 शहरों में कनेक्टिविटी एवं पहुंच में सुधार से **व्यापार, निवेश व पर्यटन** को सुविधाजनक बनाया जा सकता है।
- **संतुलित शहरीकरण: इन शहरों में अवसर पैदा करके** टियर-1 शहरों की तरफ हो रहे प्रवास की प्रवृत्ति को उलटा जा सकता है।

आगे की राह

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा:** अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को वित्त-पोषित करने और उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए।
- उद्योगों को क्षेत्रक-विशिष्ट लक्ष्य-आधारित प्रोत्साहन प्रदान करना और समर्पित निवेश संवर्धन एजेंसियों की स्थापना करना।
- शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग के जरिए कौशल विकास और शिक्षा को बढ़ावा।
- स्मार्ट सिटी पहल के जरिए **डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना।**
- निवेश को आकर्षित करने के लिए व्यवसाय को वित्तीय प्रोत्साहन और भूमि आवंटन।
- रहने योग्य शहर, **किफायती आवास बनाकर जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना।**
- **मार्केटिंग और ब्रांडिंग:** शहरों की ब्रांडिंग, स्थानीय सरकार की भागीदारी को बढ़ावा और निवेशकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम के जरिए।

बॉक्स, चित्र और टेबल

बॉक्स 1.1: जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण 2

बॉक्स 2.1: टियर-2 और टियर-3 शहरों में तेजी से बढ़ता स्टार्ट-अप इकोसिस्टम 3

बॉक्स 3.1: टियर-2 और टियर-3 शहरों में पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने में स्थानीय स्वशासन की भूमिका 4

टेबल 5.1: टियर-2 और टियर-3 शहरों में संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की गई सरकारी पहलें 5

टेबल 5.2 तेजी से बढ़ते टियर-2 और टियर-3 शहरों के उदाहरण 7